(ग) और (घ) : रोजगार के पात्र स्थानीय लोगों को रोजगार सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार ने मार्गदर्शी नियम जारी किए हैं तथा रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के अंतर्गत इस आशय का नियम बनाया है कि अधिकतम रु० 800/—प्रतिमाह के वेतनमान के सभी खाली पदों की सूचना स्थानीय रोजगार कार्यालय को दी जाए जहां आमतौर पर रोजगार के इच्छुक आस-पास के क्षेत्रों के लोगों के नाम दर्ज होते है । उपर्युक्त पदों पर अन्य स्रोतों से भर्ती की जा सकती है जब स्थानीय रोजगार कार्यालय द्वारा उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने के बारे में लिखित प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए ।

हिन्दी के प्रयोग के बारे में परिपत्र जारी किया जाना

2746. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने और "सम्पर्क भाषा" का विकास करने के लिये 1977 से बहुत परिपत्र जारी किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और जारी किए जाने की तारीख क्या हैं और क्या उनकी प्रतियां सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) वर्ष 1980 के पश्चात् से उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है जिन्होंने इन परिपत्रों के आदेशों का पालन नहीं किया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बहुत से परिपत्र जारी किए गए हैं ।

(ख) ऐसे सभी परिपत्रों की संख्या और जारी करने की तिथियां "हिन्दी के प्रयोग संबंधी आदेशों का संकलन (द्वितीय संस्करण)" में छप चुकी हैं तथा संसद के पुस्तकालय में इस संस्करण की प्रतियों राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1008 दिनांक 6 मई, 1982 के उत्तर के संदर्भ में उपलब्ध करा दी गई थीं ।

(ग) सरकार राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए किसी दंड का सहारा लेने के बजाए अनुनय विनय और प्रोत्साहन का मार्ग अपनाना अधिक उपयुक्त समझती है । इसलिए किसी अधिकारों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

सुजुकी का मारुति के साथ किए गए करार की तुलना में पाकिस्तान आटोमोबाइल कारपोरेशन के साथ किया गया करार

2747. **श्री बाबू राव परांजपे :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स सुजुकी ने, जिसने यात्री कार के उत्पादन के लिए मारुति लिमिटेड के साथ सहयोग-करार किया है ; जून, 1982 में पाकिस्तान आटोमोबाइल कारपोरेशन, के साथ भी एक करार किया है, जिसके अन्तर्गत 57 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई जाएगी तथा 25 हजार कार आदि प्रतिवर्ष बनाई जाएगी और कार का अनुमानित मूल्य लगभग 25 हजार रुपये होगा ;

(ख) यदि हां, तो जापान की सुजुकी कम्पनी द्वारा भारत की मारूति कम्पनी के साथ किए गए करार तथा उसके दो महीने बाद पाकिस्तान की सरकारी कम्पनी के साथ किए गए करार से सम्बन्धित (1) पूंजी निवेश, (2) उत्पादन क्षमता, (3) कार के अनुमानित मूल्य के तुलनात्मक आंकड़े क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा खान और इस्पात मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) (क) से (ग). यह बताया जाता है कि जापान की मै० सुजुकी मोटर कम्पनी लिमिटेड ने पाकिस्तान में गाड़ियों के निर्माण के लिए समझौता किया है। मारूति उद्योग लिमिटेड परियोजना की पाकिस्तान की परियोजना से तुलना करना उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि परियोजना का विवरण, पैरामीटर और क्षेत्र समान नहीं है । मारूति परियोजना में निर्माण की प्रौद्योगिकी और कारखाने के अन्दर निर्माण सुविधायें पाकिस्तानी परियोजना से भिन्न है । पाकिस्तान में कार के प्रस्तावित मूल्य के बारे में प्रमाणित ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं । किन्तु समझा जाता है कि प्रश्नगत गाड़ी की कीमत लगभग 50,000 पाकिस्तानी रुपये हो सकती है ।

Cancellation of Licence of Newsprint Factory at Neizla in H.P.

2748. PROF. NARAIN CHAND PARASHAR: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the licence for opening a newsprint paper factory at Neizla in Bilaspur district of Himachal Pradesh was cancelled during the last five years;

(b) if so, the exact date and the reasons for which the licence was cancelled and the name of the firm to which it was allotted;

(c) whether any other firm/company or industralist has offered or has been contacted to set up the mill; and

(d) if so, the names and the outcome thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY AND STEEL AND MINES (SHRI NARAYAN DATT TIWARI): (a) and (b). Yes, Sir. An Industrial licence was issued in 1961 to M/s. Ballarpur Paper & Straw Board Ltd. (Shree Gopal Division) for setting up a 60,000 tpa newsprint factory at Neilla (H.P.). Since the party could not implement the scheme, the licence was revoked on 27.4.77.

(c) and (d). A letter of intent was issued to Shri B. D. Somani in 1976 for establishing a newsprint/paper mill in District: Bilaspur (H.P.). This was also cancelled on 27.3.81 the party could not implement the same.

नई योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश को धन राशि

2749. श्री हरीश कुमार गंगवार : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नई योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को धनराशि दी है ;

(ख) यदि हां, तो नई योजनाओं के लिए इस राशि में से बरेली और पीलीभीत जिलों को कितनी राशि दी जाएगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?